

ई-समाचार पत्र



तिथि: 07.09.2021 , मंगलवार

ग्लोबल पावर 10

एक साप्ताहिक समाचार

एकजुट - संगठित-समृद्ध

The true companion of Patriots

देशभक्तों का सच्चा साथी

दिनांक 31.08.2021 से 06.09.2021 तक (भोपाल ई-समाचार प्रिंट: संस्करण: 7 of 2021) पेज 25

पंजीकरण संख्या: MPHIN/2012/46576 DATED 23.11.2012.

Registered under : Press and Registration of Books Act. 1867.

पंजीकृत : प्रेस और रजिस्ट्रेशनियो ऑफ बुक्स एक्ट. 1867. के तहत पंजीकृत.

कीमत: 10 रुपये प्रति कॉपी रियायती 80% 2 रुपए प्रति ई-प्रिंट pdf ।

साप्ताहिक समाचार ई-पेपर

वीयूबी वेबसाइट डोमेन: vindhyanchaluniversity.in

मुख्य संपादक: श्री 1008 आचार्य डॉ. रतन लाल जी बाथम, धर्म शिरोमणि।

मुद्रित रचित और प्रकाशित: श्री 1008 आचार्य डॉ. रतन लाल जी बाथम, धर्म शिरोमणि द्वारा प्रकाशित .

स्थान: भोपाल.

संरक्षण: ओर्विंध्याचलास्य शैक्षणिक एवम समाजिक संस्था, भोपाल - 4620 42 (ओवीएसएस भोपाल).

संरक्षण: विंध्याचल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय भोपाल (VUB भोपाल) .

संपर्क कार्यालय: 7260892959, 7049098074

Payment detail: 7049098074

www.vindhyanchaluniversity.in

Email: globalpower10@vindhyanchaluniversity.in

प्रिय पाठकों साप्ताहिक ई-पेपर: ग्लोबल पावर-10: 2021 से संबंधित सूचना हैं:

1. समाचार पत्र का नाम : ग्लोबल पावर-10
2. पंजीकरण नंबर : MPHIN/2012/46576 दिनांक 23 नवंबर २०१२ ।
3. डोमेन नाम : www.vindhyanchaluniversity.in
4. समाचार ई-पेपर साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है भोपाल से हर मंगलवार को .
5. इसकी कीमत 10.00 रुपये है इस पर 80% की छूट दी गई है, इसलिए प्रिंट ई-पेपर ग्लोबल पावर-10 की कीमत 2 रुपये प्रति पीडीएफ है 8 TO 34 पृष्ठों के लिए। ऑफ़र और मूल्य निर्धारण बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।

6. सदस्यता वार्षिक आधार पर भुगतान की जाने वाली राशि 100.00 रुपये होगी

: Payment detail: **7049098074** इस नंबर पर आप

गूगल फोन Pay द्वारा भुगतान कर सकते हैं OR हमारी वित्तीय सलाहकार कंपनी को एनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा अपनी सदस्यता का भुगतान कर सकते हैं :

ए के सिव्योरिटीज ए/सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए/सी नंबर

00011045080223

आईएफएससी कोड: SBIN0006319

7. ई-प्रिंट ग्लोबल पावर टेन -10 द्वारा ई मेल द्वारा pdf भेजा

जाएगा। इस पेपर का ईमेल है : globalpower10@vindhyanchaluniversity.in

8. सम्मानित पाठक /निजी/सरकारी आयोजन / इस ई-न्यूज वीकली पेपर (केवल पीडीएफ फॉर्म में ई-प्रिंट) की सदस्यता लेने ऊपर के आइटम 6 में दिए गए Mobile Number: 7049098074/ बैंक खाते में सदस्यता शुल्क भेज सकते हैं ।

9 संपर्क कार्यालय: 7260892959, 7049098074

LASSIFIED: विज्ञापन :

विज्ञापन हेतु संपर्क : संपत्ति के बिक्री / खरीद के लिए, घर किराए पर किराया देने या लेने के लिये कृपया संपर्क करें

10. शादी के विज्ञापन दूल्हा और दुल्हन के लिए विज्ञापन, 7049098074



7260892959, संपर्क करें.

11. नौकरी व्यवसाय सार्वजनिक नोटिस, कंपनी एजीएम या किसी भी नोटिस के लिए विज्ञापन हेतु संपर्क करें. संपर्क कार्यालय: 7260892959, 7049098074

1. ईमेल पर पत्राचार करें: globalpower10@vindhyanchaluniversity.in

12. मार्गदर्शन के लिए कृपया ध्यान दें: विज्ञापन हेतु 4 प्रविष्टि (insertion) के लिए कीमत 25 से 50 शब्दों के लिए 500 रुपये है। फोटो ग्राफ पास पोर्ट साइज के साथ अतिरिक्त लागत 500.00 रुपये प्रति फोटो कीमत होगी

1. व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विज्ञापन के लिए कार्यालय फोन या ईमेल globalpower10@vindhyanchaluniversity.in पर संपर्क करें.
- 13.1 किसी भी विज्ञापन का काल इस साप्ताहिक समाचार प्रिंट के 3 महीने से अधिक प्रकाशन नहीं होगा.
- 13.2 यदि समय अवधि 3 महीने से अधिक है तो शुल्क दोहराया जाएगा।



ग्लोबल पावर 10 ई- पेपर मैनेजमेंट.

मंगलवार भोपाल 06.09.2021

ग्लोबल पावर 10 संपादकीय



संपादकीय: आचार्य जी रतन लाल बाथम

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान अपर्याप्त पाया गया कौन सा पार्टी अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति १९८९ पर अत्याचार निवारण को लागू नहीं करने का दोषी है ।

एससी/एसटी एक्ट 1989 वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू (एससी/एसटी एक्ट 1989 का इतिहास)

भारत की राज्य (dominion state 15.8.1947) स्थिति के बाद सभी नागरिकों की रक्षा के लिए संविधान बनाया गया था । लेकिन नस्लवाद की जाति व्यवस्था की जड़ भारत में इतनी गहराई तक चली गई है कि शोषित वर्ग के साथ अमानवीय अत्याचार कम नहीं हुए 8वीं सदी में बसने वाले स्वयं को सावरना सनातनी कहते हैं और समाज का भ्रम पैदा करने के लिए उन्हें अरबी शब्द हिंदू प्रचारित करते हैं । इन घटनाओं से चिंतित तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एससी/एसटी जातियों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए जरूरी कानून बनाने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया था। 15 अगस्त, १९८७ को डोमिनर दिवस दिवस पर दिए गए भाषण में उन्होंने घोषणा की थी कि अत्याचारों की जांच के लिए यदि आवश्यक हुआ तो एक अधिनियम पारित किया जाएगा । इसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद के दोनों सदनों से 11 सितंबर 1989 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का विधेयक पारित कर दिया। लेकिन इस एक्ट के लागू होने से पहले ही लोकसभा के लिए आम चुनाव शुरू हो गया है। उस चुनाव में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला था । नेशनल फ्रंट नई गठबंधन सरकार से 30 जनवरी 1990 से इस नियम को लागू किया। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों को परेशान करता है। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 23 Articles. So थे, इस एससी/एसटी अधिनियम 1989 को बनाने का मुख्य श्रेय कांग्रेस को जाता है, जबकि इस एससी/एसटी अधिनियम 1989 को। बाद में इस अधिनियम में 23 जून 2014 को संशोधन किया गया। अगस्त 2018 में केंद्र की भाजपा सरकार ने इस एक्ट को खोखला बना दिया। इस अधिनियम में कई अनुच्छेदों को जोड़कर, यह अधिनियम गैर-अग्रिम जमानत अधिनियम के लिए हो जाता है।

2.9.21 GP10 प्रस्तुत करता है

स्थिति में सुधार के लिए अदालती कार्रवाई का स्वागत किया है



मान्य सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान दिल्ली में तबलीगी जमात सभा की घटना के सांप्रदायिककरण की आलोचना की ।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है? हर चीज को सांप्रदायिक एंगल दिया जाता है। वेब पोर्टल किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। यदि आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी फर्जी खबरें और झूठी जानकारी घूम रही है। कोई भी ऐसा करना शुरू कर सकता है ।

सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ तबलीगी जमात मामले के दौरान कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल और गलत रिपोर्टिंग के संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रही थी । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या केंद्र द्वारा सुझाए गए नियामक आयोग का गठन किया गया था । समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीसा) ने कहा कि उन्होंने २०२१ में नियमों में संशोधन को चुनौती दी है ।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सही जानकारी पाने के लिए प्रेस की आजादी और नागरिकों के अधिकार के बीच संतुलन है। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि

कोई अप्रिय सूचना या समाचार प्रसारित न हो । प्रसारकों और वेब पोर्टलों के लिए नियम बनाए गए हैं ।

2

2.9.21 Thu 2.9.21 GP10 प्रस्तुत करता है



टाइगर संरक्षण-एक वैश्विक सफलता

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ने 1970 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार के पहली बार बाघ संरक्षण कार्यक्रम परियोजना बाघों को सहायता प्रदान करके बाघ संरक्षण शुरू किया । 1990 के दशक में, WWF इंडिया ने एक केंद्रित बाघ संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया और वर्तमान में छह बाघ परिदृश्यों में काम करता है: तराई आर्क, सुंदरवन, मध्य भारत, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी घाट-नीलगिरी और पश्चिमी भारत टाइगर परिदृश्य ।

वर्गीकृत: विज्ञापन

दिनांक 2.9.21 गुरुवार 2.9.21



अभिनेता सिद्धार्थ का ४० में निधन

सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया, पुलिस की एक टीम जांच के लिए शुक्ला के आवास पर मौजूद है।

प्रिय पाठकों कृपया आगे पढ़ने के लिए सदस्यता लें

प फोन पे द्वारा भुगतान कर सकते हैं: मोब नंबर 7049098074 या SEND EMAIL FOR REQUEST OF SUBSCRIPTION to receive you pdf copy by email. after transfer of Rs 100.00 (Rs. One hundred) to the payment details given below:

हमारी वित्तीय सलाहकार कंपनी को एनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा अपनी सदस्यता का भुगतान करें:

ए के सिक्योरिटीज ए/सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए/सी नंबर
00011045080223

आईएफएससी कोड: SBIN0006319
धोलेपाटिल रोड बंड गार्डे पुणे-411001
महाराष्ट्र

ग्लोबल पावर 10 मैनेजमेंट

6.9.21 अफगन संकट पर सारांश के लिए सोम रिपोर्ट

टीम GP10

काबुल में अमेरिकी दौरे का अंत



प्रमुख कारण अमेरिका अफगानिस्तान में खो दिया

9/11 के बाद, अफगानिस्तान में लगभग 20 साल के लंबे युद्ध का सबसे चौंकाने वाला दिन 2 मई, २०११ था, जब अमेरिकी नौसेना के जवानों ने पाकिस्तान में एक ऊंची दीवारों वाले परिसर में झपट्टा मारा और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। यह कुछ है कि शुरू से ही बहुत ज्यादा स्पष्ट किया गया था पता चला: जब अमेरिका 7 अक्टूबर, २००१ को अफगानिस्तान पर हमला किया, यह भी पाकिस्तान, अपने अगले दरवाजे

पड़ोसी के साथ युद्ध के लिए गया । अमेरिका की धरती पर सबसे घातक हमला करने वाले बिन लादेन ने **एबटाबाद के बाहरी इलाके में छिपे**

हुएथे। 200000 का शहर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सीमा के अंदर १०० मील की दूरी पर है, बस पाकिस्तान सैन्य अकादमी से सड़क के नीचे-उस राष्ट्र के पश्चिम बिंदु ।

लेकिन पाकिस्तान ने बिन लादेन को पनाह देना इतना अजीब नहीं था । आखिरकार, पाकिस्तान लादेन के अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान

विद्रोहियों को **सुरक्षित पनाहगाह की पेशकश कर रहा था**, जब से अमेरिकी सरकार ने 10 साल पहले

अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से बाहर कर दिया था-बिन लादेन अभयारण्य की पेशकश के लिए । पाकिस्तान के दोहरे व्यवहार के बारे में इस्लामाबाद से काफी खंडन और वाशिंगटन से जानबूझकर अज्ञानता थी । अगर इस्लामाबाद में नेताओं को पता नहीं था, यह था क्योंकि वे जानना नहीं चाहता था । लेकिन युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान दो तरीकों से अमेरिकी दुश्मनों को सुकर देगा: उन्हें अफगानिस्तान के अंदर आपूर्ति करके, जबकि वे वहां लड़ रहे थे, और उन्हें पाकिस्तान के अंदर छुपा कर जब वे नहीं थे । कि छाती घाव है कि

अपने सबसे लंबे समय तक युद्ध में प् अमेरिका ने प्रतिनिधित्व किया ।

1 मई, २०११ की सुबह एन, ज्यादातर अमेरिकियों एबटाबाद के बारे में कभी नहीं सुना था । उस रात तक पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के पहाड़ों के पास धूल भरे मिडसाइज शहर दुनिया की सबसे बड़ी कहानी का केंद्र था । अमेरिकी नौसेना के जवानों की एक टीम सिर्फ रात के अंधेरे में वहां एक उच्च दीवारों हवेली पर हेलीकाप्टर से उतरा था, दुनिया के सबसे शिकार आदमी स्थित है और उसे मार डाला ।

ओसामा बिन लादेन, जो इस सप्ताहांत 10 साल पहले हुई थी, को ट्रैक और अंजाम देने का प्रयास आधुनिक अमेरिकी इतिहास में सबसे बारीकी से आयोजित परिचालन रहस्य था- एक बेहद संवेदनशील, राजनीतिक रूप से भरा हुआ और शारीरिक रूप से जोखिम भरा मिशन जिसमें अंतरराष्ट्रीय हिंसा और आतंक के एक आइकन को निशाना बनाने के लिए एक कथित अमेरिकी सहयोगी के संप्रभु क्षेत्र का उल्लंघन शामिल था ।

दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से रखा गया था- इसे एक शक्तिशाली पश्तून आदिवासी विद्रोह द्वारा गैर-डिप्लो भाषा में *पराजित किया* गया था ।

अफगानिस्तान के 390 लाख लोगों में से ४०% से ज्यादा लोगों को बनाने वाले पश्तूनों ने पेंटागन को एएफ-पाक बॉर्डर क्या कहते हैं । उन्होंने अल-कायदा और तालिबान को अमेरिकी बंदूकों की पहुंच से बाहर पाकिस्तान की ओर से पनाह दी । यह एक 21 वीं सदी हो ची मिंह ट्रेल में है कि मना, पहाड़ीसीमा, लाओस और कंबोडिया

के माध्यम से आपूर्ति मार्ग है कि दक्षिण वियतनाम में कम्युनिस्ट विद्रोह एक आधी सदी पहले बदल गया ।

अमेरिकी अधिकारियों को पता था कि पाकिस्तान युद्ध के शुरुआती दिनों से एक चुनौती है लेकिन उज्ज्वल पक्ष पर देखने के लिए चुना है । अमेरिका-पाकिस्तान के संबंध

१९९० में अलग हो गए, अमेरिका के निष्कर्ष के बाद इस्लामाबाद गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था (जिसके लिए एक बहादुर सीआईए विश्लेषक ने भारी कीमत चुकाई) । एक दशक से भी ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच सैन्य-से-सैन्य संबंध नहीं थे । "प्रतिबंध काम नहीं किया," क्रिस्टीना Rocca, समय पर इस क्षेत्र के लिए शीर्ष अमेरिकी राजनयिक, २००३ में कहा । "हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से हमारे हाथ बांधने का एक बेहतर तरीका होना चाहिए था । देशों ने फिर से एक चारी संबंध फिर से शुरू किया ।

वाशिंगटन का मानना था कि अपने ही देश में विद्रोह गहराने और अमेरिकी सहायता में \$३०,०,०,००० से अधिक के विद्रोह को लेकर पाकिस्तानी सरकार का डर अफगानिस्तान के पूर्वी पड़ोसी को बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करने से रखेगा ।

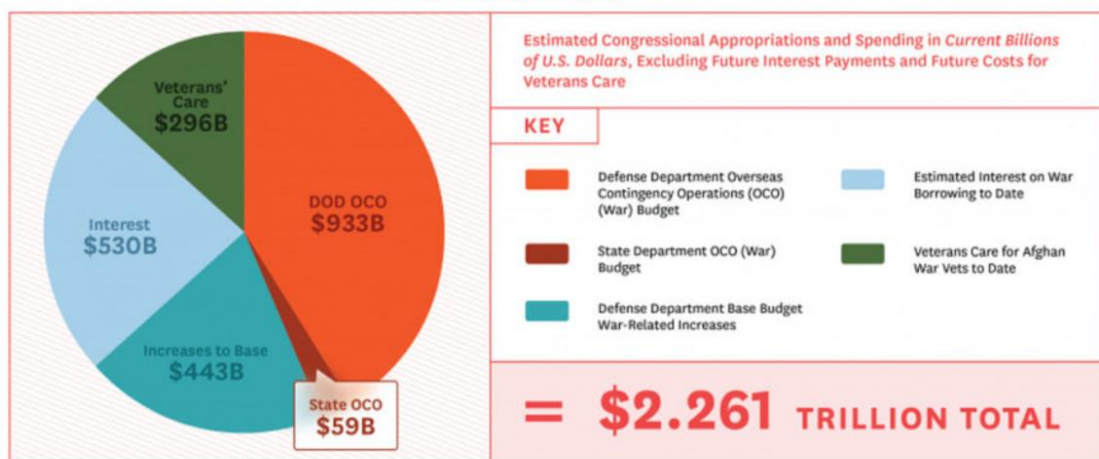
लेकिन हर कदम के लिए पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद के लिए लिया, यह कई और अधिक है कि दुश्मन को ऑक्सीजन दिया ले लिया । "यदि आपके पाकिस्तानी सहयोगी कहते हैं कि आप अपने देश के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन केवल रात में और दिन में कोई दिखाई पदचिह्न छोड़, इस तरह की बाधाओं को अपने विकल्प । ठीक है? " मरीन कोर के तत्कालीन सहायक कमांडेंट जनरल रॉबर्ट मैग्रस ने २००६ में कहा था । "ऐसा नहीं है कि वे वास्तव में ऐसा करेंगे?" एक रिपोर्टर

interjected । "ठीक है," मैग्रेस हंसी से कहा, "ऐसा नहीं है कि वे करेंगे."

सुरक्षित ठिकाने क्या प्रदान करते हैं? "ज्ञान और आराम और रिफिट और योजना और बस, तुम के दबाव में नहीं हो पाया जा रहा है और शिकार और अपने आप को बचाने के लिए," सेना के लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस Metz, पेंटागन की दुकान के तत्कालीन प्रमुख तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों को हराने के लिए स्थापित, २००८ में कहा । "यह आपको अन्य चीजों को करने के लिए समय और ऊर्जा देता है ।

अमेरिकी अधिकारियों [का कहना](#) है कि अफगानिस्तान में अभी भी २,५०० सैनिकों और १८,००० अमेरिकी ठेकेदारों घर आना शुरू कर सकते हैं क्योंकि युद्ध के 20 साल खतरे को कम कर दिया है अल कायदा और तालिबान अब मुद्रा (अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या २०११ में १८,००० पर [नुकीला](#)) । अमेरिका का कहना है कि वह इस बात की निगरानी करेगा कि देश के बाहर के पदों से अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और अगर जरूरी हो तो हमला इस तरह से रखना होगा ।

U.S. Costs to Date for the [War in Afghanistan](#), in \$ Billions, 2001–2021



(Source: *Costs of War Project*)

06.09.21 सोमवार GP10 रिपोर्ट

15 साल की लड़की (निर्भया न बदला नाम) का अपहरण



कर बंधक बनाकर रखा और बेचा



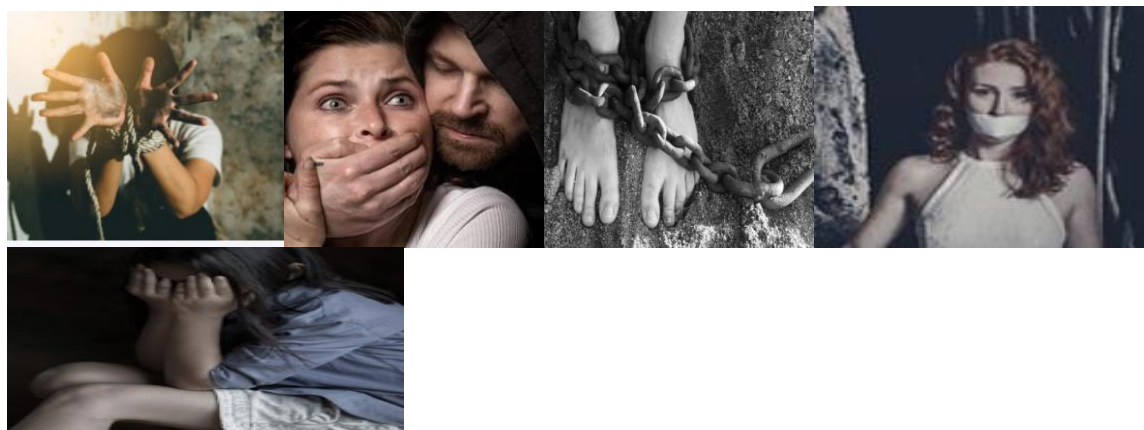
इस अपराध से पूरा भारत स्तब्ध है।

मध्य प्रदेश में अपहरण और रैप की सुनामी;
भारत में मूल निवासी पर भयावह अत्याचार
की आग देश को झटके; देश को झटके; देश
को झटके; देश को झटके; वही राजनीतिक
अपराध चरम पर हैं मध्य प्रदेश में अपहरण
और रैप की सुनामी; भारत में मूल निवासी
पर भयावह अत्याचार की आग देश को
झटके; देश को झटके; देश को झटके;
देश को झटके;

15 साल की लड़की (निर्भया न बदला नाम) का अपहरण कर बंधक बनाकर रखा और बेचा . अपराधी

आरोपी शर्मा एक ब्राह्मण फरार और उसके गिरोह फरार ।

मध्य प्रदेश कांग्रेस में सरकार जैसी कोई बात नहीं है और भाजपा ने पाकिस्तानी आतंकी से सबसे ज्यादा भारत को तबाह कर दिया । आधी स्वतंत्रता का मतलब है 15.08.1947 को भारत का आधी स्वतंत्रता प्रभुत्व स्थितिडोमिनर के बाद से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर अपराध में कई गुना वृद्धि हुई औरनिरंतर अपराधी अपराध कर रहे हैं । पाकिस्तानी आतंकी ने कश्मीरी पंडितों को बाहर धकेल दिया लेकिन भारतीय देसी आतंकवादी जम्बुदीप से पूरे भारत को बाहर निकाल रहे हैं । भारत के लोग भाजपा और कांग्रेस के अपहरण बलात्कार और बैंक लूट के शासन से नाराज मर चुके हैं, अपराध की यह सुनामी भारत में कब रुकेगी यह भी भगवान जानता है ।

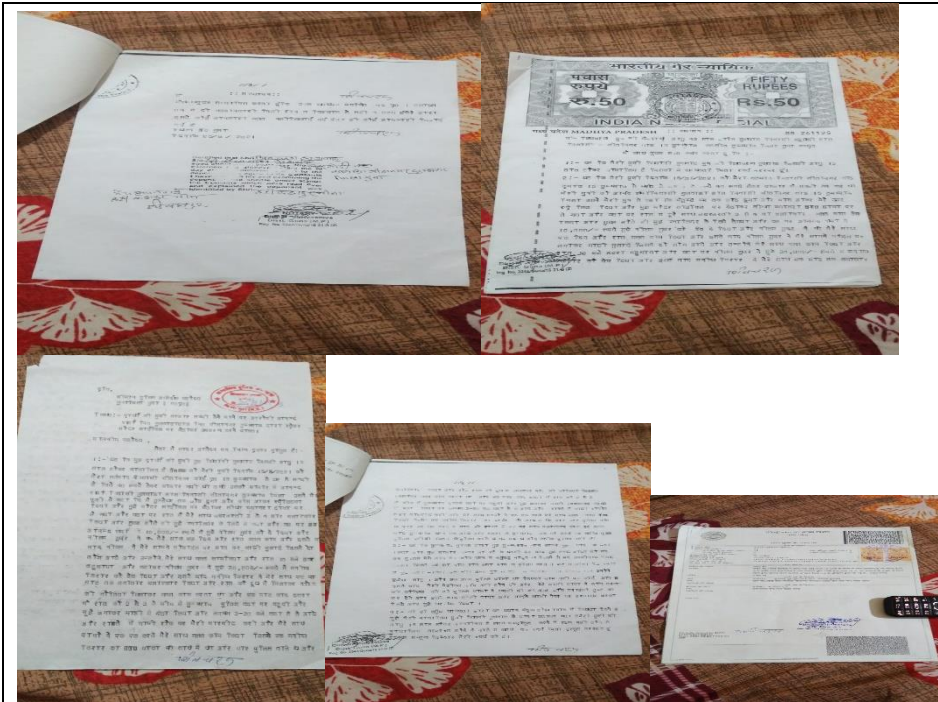


गुना संवाददाताओं की रिपोर्ट: दिनांक 5.9.21
GP10 रिपोर्ट।

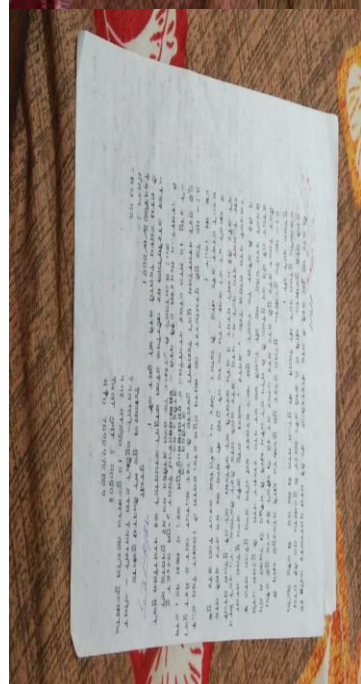
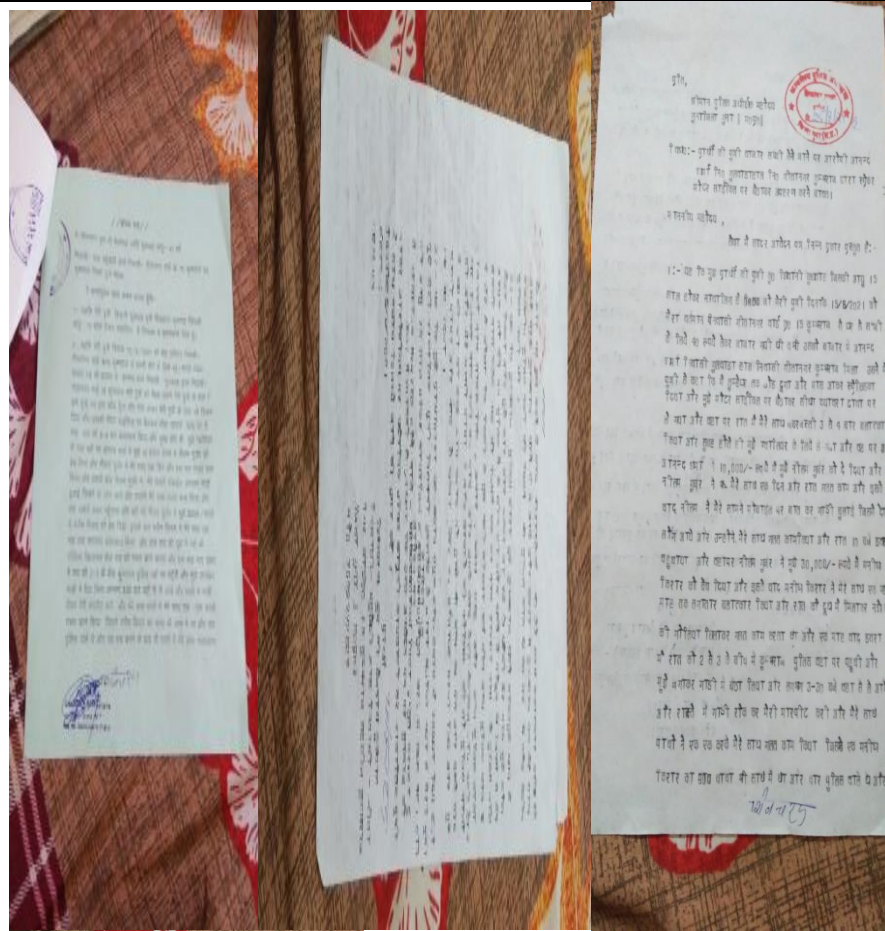
हमला मध्य प्रदेश किडनैपर्स और बलात्कारी के लिए सुरक्षित स्वर्ग बन गया । बिना किसी डर के अपराधी भटक रहे हैं पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं है। लोग डर के मारे जी रहे हैं और अपने जानमाल की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश को छोड़ रहे हैं। लोग न्याय और सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र राज्य में जा रहे हैं।

एक सबसे बड़ा अपराध किया गया और हुआ पुलिस घोडे बिक्री कर र सो रही है । प्लोइटिकल प्रोटेक्शन से इनकार नहीं किया जाता है ।

मध्य प्रदेश किडनैपिंग और रेप प्रदेश बन गया भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक निहित मर्जी के साथ अपराधों को हवा देकर देश को खोखला कर रहे हैं । सांसद अपराधियों का स्वर्ग है।



इस अपराध से पूरा भारत स्तब्ध है।



अधिक जानकारी अगले सप्ताह में करेंगे

ठोस सबूत के बावजूद पुलिस सो रही है। प्रशासन और सीएम 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लोग बुरी तरह कुचल रहे हैं. अत्याचार और कुचलने का दौर चरम पर है।

GP10 NEWS
Mon 6.9.21



आधार कार्ड अपडेट: आधिकारिक आधार फोटो को एक नए के साथ बदलें - विवरण देखें

यूआईडीएआई ने आधार कार्ड धारकों को सरल और आसान चरणों में अपनी आधिकारिक तस्वीर बदलने की अनुमति दी।

आधार कार्ड पर आधिकारिक फोटो कैसे बदलें?

यूआईडीएआई आधार कार्ड पर अपनी फोटो बदलना देख रहे लोगों को अपना अनुरोध ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद, व्यक्ति को अपने घर के पास एक यूआईडीएआई केंद्र पर जाने की आवश्यकता होगी ताकि एक नई आधिकारिक तस्वीर कैप्चर की जा सके।

यहां अपने आधार कार्ड की तस्वीर अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रियाओं के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है।

1. चरण 1: आधिकारिक यूआईडीएआई वेबसाइट पर जाएं
2. दूसरा चरण: आधार नामांकन फॉर्म डाउनलोड करें
3. चरण 3: आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें
4. चरण 4: अपने करीबी आधार नामांकन केंद्र पर जाएं
5. चरण 5: आधार नामांकन कार्यकारिणी के साथ फॉर्म जमा करें
6. चरण 6: बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से अपना विवरण सत्यापित करें
7. चरण 7: आधार सेवा केंद्र में कैप्चर की गई एक नई आधिकारिक तस्वीर प्राप्त करें
8. चरण 8: अपनी तस्वीर अपडेट कराने के लिए शुल्क का भुगतान करें (25 रुपये + जीएसटी)
9. चरण 9। पावती पर्ची प्राप्त करें जो आपका अपडेट अनुरोध नंबर (यूआरएन) दिखाती है
10. चरण 10। आप यूआईडीएआई वेबसाइट पर आधिकारिक फोटोग्राफ अपडेट अनुरोध की स्थिति की जांच करने के लिए इस यूआरएन का उपयोग कर सकते हैं
11. चरण 11: नई आधिकारिक तस्वीर के साथ आधार कार्ड ई-कॉपी डाउनलोड करें
12. चरण 12: एक नए भौतिक पीवीसी आधार कार्ड के लिए अनुरोध करने के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट पर आवेदन करें

यूआईडीएआई की वेबसाइट न केवल प्रति पर प्रदर्शित तस्वीर को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करती है

दिनांक 6.9.21 सोमवार GP10 दृश्य की व्यवस्था



इथियोपिया हॉरर जारी है एथियोपिया
गृहयुद्ध में जल रहा है

6.9.21 from wion

**जातीय सफाई: इथियोपिया के बच्चों, यातना
शिविरों में महिलाओं को फेंकने बलों,
सामूहिक कब्र का निर्माण, रिपोर्ट कहते हैं,**

उत्तरी टिगरे क्षेत्र में एक प्रमुख शहर पर कब्जा करने वाली इथियोपिया की सेनाएं बच्चों और महिलाओं सहित मूल लोगों की जातीय सफाई में लिप्त हैं, उन्हें अस्थायी एकाग्रता शिविरों में फेंककर और विकृत शवों को सामूहिक कब्र में डंप करके, गवाहों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में दावा किया गया है ।

टेलीग्राफ के अनुसार, जातीय Amhara बलों "घर-घर" जा रहा है किसी को भी, जो इथियोपिया के गृहयुद्ध में

जनसंख्या सफाई के नवीनतम दुःखद सबूत में जातीय तिग्रायन है दौर ।

"फेवेन Berhe एक निर्दोष निवासी जो एक छोटी सी दुकान के स्वामित्व में था । टेलीग्राफ ने ४० वर्षीय पीड़िता को जानने वाले एक निवासी के हवाले से कहा, वे उसे टेकेज़ नदी में ले गए और उसे गोली मार दी ।

"इससे पहले कि वे उसे मार डाला, वे उसकी आंखें हटा दिया और उसके पैर काट दिया । निवासी ने दावा किया, उन्होंने किसी को भी उसके शव को लेने और उसे दफनाने नहीं दिया ।

जातीय सफाई एक युद्ध है कि इथियोपिया के संघीय सैनिकों और Tigray पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF), जो Tigray क्षेत्र को नियंत्रित करता है के प्रति वफादार बलों के बीच टूट गया इस प्रकार है । हजारों की मौत हो चुकी है और 2000000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा है ।

ह्यूमेरा शहर में इरिट्रिया और सूडान के साथ इथियोपिया की सीमा के पास लगभग ५000000 की आबादी है । अपने रणनीतिक स्थान के कारण, यह उन पहले स्थानों में से एक था जब इथियोपिया के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री अबी अहमद और इरिट्रिया के तानाशाह ने नवंबर में टिगरे की क्षेत्रीय सरकार को कुचलने के लिए एक पिनसर हमला शुरू किया था ।

हालांकि जून में टिगरे बलों ने इथियोपिया और सहयोगी सेनाओं के पीछे हट जाने के रूप में इस क्षेत्र के बहुत से पुनः दावा किया, पश्चिमी टिग्रे अभी भी इथियोपिया के पड़ोसी अहारा क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित है, जिन्होंने कई जातीय तिग्रयानों को मंजूरी दे दी है, जबकि कहा कि भूमि ऐतिहासिक रूप से उनकी है ।

पिछले साल से, जातीय Amhara बलों, जो एक पड़ोसी क्षेत्र से जय हो और नोबेल पुरस्कार विजेता से संबद्ध हैं, ने पश्चिमी तिगरे के swathes के साथ-साथ शहर को नियंत्रित किया है ।

सूत्रों ने टेलीग्राफ को बताया कि जून के अंत में तिगरायन रक्षा बलों द्वारा जीत की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला के बाद, हुमेरा में कब्जा करने वाली ताकतों ने शहर में जातीय तिगरायंस को शुद्ध करना शुरू कर दिया ।

15 जुलाई को अहारा सेनाओं ने हुमेरा के मुख्य नगर पालिका हॉल में एक जनसभा आयोजित की, जिसमें उनके द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में तिगरानियों के भाग्य का फैसला किया गया ।

"उन्होंने यह कहा-हमें शहर के सभी तिगरायन निवासियों को खत्म करना चाहिए । एक आदमी है जो क्लैई ने कहा, हम उन सब को शुद्ध करना चाहिए

06.09.21 Mon



ओवल जीत टेस्ट क्रिकेट में भारत के प्रभुत्व के संकेत के रूप में है

भारत की ओवल में 4th टेस्ट 157 रन से जीत , 50 साल बाद जीत भारत ने 1971 में हासिल की थी।
4 टेस्ट के बाद 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 भारत ने अपराजित बढ़त हासिल की ।

भारत के गेंदबाजों ने सोमवार को ओवल में चौथे टेस्ट के पांचवें दिन इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम को 157 रन से जीतकर मैच अपने पास पहुंचा दिया। पहली पारी में ९९ रन की बढ़त मानने के बावजूद भारत इस मैच में पीछे से आकर जीत पक्की कर रहा था और 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त ले रहा है।



पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020

भारत ने 24 अगस्त से 5 सितंबर २०२१ तक टोक्यो, जापान में २०२० ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लिया। **भारतीय** एथलीट १९८४ के बाद से ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के हर संस्करण में दिखाई दिए हैं, हालांकि उन्होंने १९६८ ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में अपनी आधिकारिक शुरुआत की।

प्रतियोगियों: 9 खेलों में ५४

भारत 24^{वें} स्थान पर रहा . अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन।



प्रमोद भगत

प्रमोद भगत ने जीता बैडमिंटन गोल्ड भारत लिए ऐतिहासिक का यह स्वर्ण एनडिया

19 पदक-भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ टोक्यो पैरालंपिक को
खत्म किया

6.9.21 Mon GP10 India news

लाठीचार्ज के विरोध में किसान करेंगे महापंचायत, डीएम बोले, इस बार अधिकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई, नहीं जाम करने देंगे हाईवे



मंगलवार को होने जा रही करनाल महापंचायत और लघु सचिवालय के घेराव को लेकर हरियाणा भारतीय किसान संघ प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा कि करनाल प्रशासन के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। किसान अपनी [पंचायत](#) के साथ आगे बढ़ेंगे। मालूम हो कि 28 अगस्त को किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ महापंचायत हो रही है।

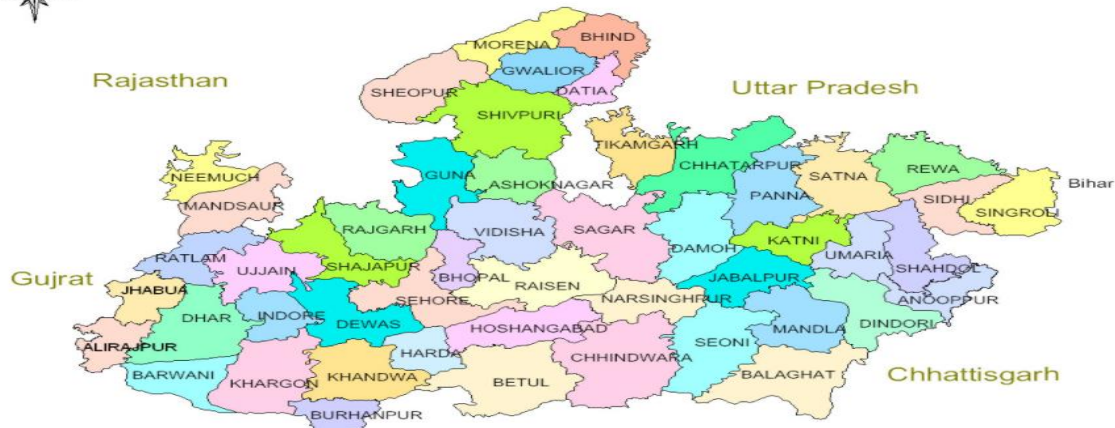
चढ़नी ने कहा कि मंगलवार को करनाल में एक विशाल पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद किसान लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा, “ किसान मंगलवार सुबह करनाल की नयी अनाज मंडी में एकत्रित होंगे।” वहीं, करनाल के डीएम निशांत कुमार यादव ने कहा, ‘हमने

किसानों के साथ बातचीत की। उनकी मांग जायज नहीं थी। कानून का उल्लंघन करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा और हमारे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम उन्हें हाईवे और लघु सचिवालय का घेराव नहीं करने देंगे।’

साथ ही साथ करनाल के एसपी गंगा राम पुनिया ने कहा, ‘फोर्स की कुल 40 कंपनियां तैनात हैं। जिसमें से बीएसएफ समेत सीएपीएफ के अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात हैं। पांच एसपी और 25 डीएसपी रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण वाहन, ड्रोन भी तैनात हैं।’ बता दें कि हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त के पुलिस लाठीचार्ज को लेकर किसानों की महापंचायत और लघु सचिवालय के घेराव की योजना के एक दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए “गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार पर काबू” के लिए करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का सोमवार को आदेश दिया।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सोमवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर मंगलवार मध्यरात्रि तक बंद रहेंगी। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत के लिए भी इंटरनेट/एसएमएस सेवाएं 7 सितंबर (सोमवार रात से मंगलवार रात तक) के लिए निलंबित कर दी गयीं। आदेश में कहा गया है कि मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार पर काबू के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। इससे पहले करनाल में मंगलवार को लघु सचिवालय का घेराव करने के किसानों के कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रशासन ने सोमवार को लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

6.9.21 Mon
With obligation



मध्य प्रदेश : 31 आइएएस और 35 आइपीएस अधिकारियों के तबादले

भोपाल, 5 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े फेरबदल में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 31 अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 14 जिलाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने 11 पुलिस अधीक्षकों सहित भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के 35 अधिकारियों के तबादले भी किए हैं।

शनिवार देर रात जारी आदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद, अशोक नगर, सागर, अलीराजपुर, धार, नरसिंहपुर, शहडोल, सीधी, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बालाघाट और निवाड़ी जिलों के 14 जिलाधिकारियों को बदल दिया है। वहीं, एक अन्य आदेश में राज्य सरकार ने 11 जिलों—रीवा, कटनी, विदिशा, निवाड़ी, मंदसौर, अलीराजपुर, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, बड़वानी एवं उमरिया के पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला कर दिया है।

इसके अलावा शहडोल, उज्जैन और बालाघाट जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों और रीवा, होशंगाबाद और जबलपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षकों के भी तबादले किए गए हैं। आदेश के अनुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रवि कुमार गुप्ता को पवन कुमार जैन के स्थान पर मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण का नया संचालक बनाया गया है। जैन अब मध्य प्रदेश होमगार्ड के महानिदेशक होंगे।

भोपाल पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआई) डीसी सागर को जी जनार्दन की जगह पर शहडोल जोन का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, जबकि जनार्दन को सागर के स्थान पर पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआई) के अतिरिक्त महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति

नई दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)।

● न्यायाधीश की पदोन्नति को रोकने की कोशिश करने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक सुस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें उच्च न्यायालय का कॉलिजियम न्यायाधीशों की वरिष्ठता, योग्यता और सरकार द्वारा उनके बारे में प्राप्त सभी सूचनाओं पर विचार करता है।

उच्चतम न्यायालय ने एक न्यायाधीश की पदोन्नति को रोकने की कोशिश करने व अदालती कार्यवाही का दुरुपयोग करने पर एक वकील पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने एक वकील की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। वकील ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ए वेंकटेश्वर रेड्डी को तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने के

प्रस्ताव पर प्रस्तुत अपने विरोध-पत्र पर विचार करने और आदेश जारी करने की मांग की थी। दरअसल, उच्चतम न्यायालय के तीन सदस्यीय कॉलिजियम ने 17 अगस्त को हुई बैठक में रेड्डी सहित छह न्यायिक अधिकारियों को तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

देश की शीर्ष अदालत, अधिवक्ता वी शैलेश सक्सेना द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र, तेलंगाना और तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता और प्रशासन) को अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विरोध-पत्र पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ए वेंकटेश्वर रेड्डी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं और कहा कि न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति नहीं

की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, 'हम याचिकाकर्ता की बेशर्मी को देखकर आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि अब वह मौजूदा याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर कर रहा है।' उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, 'हमारा विचार है कि लागत की उचित वसूली ही एकमात्र समाधान प्रतीत होता है। हम इस प्रकार रिट याचिका को खारिज करते हुए चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर फंड में पांच लाख रुपए जमा करने का निर्देश देते हैं। हम यह भी उचित समझते हैं कि बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना याचिकाकर्ता की एक सदस्य के रूप में आचरण की जांच करे और उस उद्देश्य के लिए आदेश की एक प्रति तेलंगाना की बार काउंसिल को भेजी जाए।

The back Counting of Indian Judiciary and public trust in it has started. भारतीय न्यायपालिका और इस पर जनता के विश्वास की वापस गिनती शुरू हो गई है।

GP10 observe that.

न्याय प्रणाली अपने दिनों की गिनती कर रही है आशा का कोई संकेत नहीं है देरी रॉकेट उ युग में न्याय प्रशासन सांस तोड राहा है ले जा रहा है प्रतिमान बदलाव की जरूरत है । वाद्य और वेब आधारित न्यायनिर्णयन के लिए बड़ा फंड समय की जरूरत है । बस बैंकिंग न्याय वितरण की तरह अवसर के लिए वृद्धि करने के लिए । डाटा बेस और एआई को प्रयोग किया जाए।